6.5 करोड़ श्रमिकों को एक क्लिक पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी

श्रम एवं सेवायोजन विभाग तैयार करा रहा डाटा

इस साल एक करोड़ श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के साढ़े छह करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को एक क्लिक पर सारी सुविधाओं एवं योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसके लिए उनका उनका डाटा तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। इस साल एक करोड़ श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया गया है।

प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने की योजना पर काम कर रही है। खासतौर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाओं का लाभ देने की मशक्कत की जा रही है। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में करीब 6.66 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं। इस श्रेणी में ऐसे सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिनकी मजदूरी एक लाख अस्सी हजार रुपये सालाना से कम है। ऐसे श्रमिक अपना पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अथवा स्वयं करा सकते हैं।

इसी पोर्टल के माध्यम से उन्हें योजनाओं की जानकारी एवं लाभ देने में आसानी होगी। जिन श्रमिकों का अब तक पंजीकरण हो चुका है उन्हें भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस साल एक करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक जिले को 133500 श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया है।

किसान व खेतिहर मजदूर भी करा सकते हैं पंजीकरण

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बोर्ड की योजनाओं में अहम मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है। इसके लिए फिलहाल 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है। बोर्ड की योजनाओं में 45 प्रकार के कार्य करने वाले असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा रहा था पर अब अब इस श्रेणी में छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, कागज बनाने वाले तथा गोशालाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों का भी पंजीकरण शुरू किया जा रहा है।